Distillation at Digboi has been appraised by the Scientific Advisory Committee of the Ministry of Petroleum and Natural Gas. The proposal is in feasibility stage.

Strike by employees of BPCL and HPCL

2534. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of Bharat Petroleum Corporation Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited Bombay went on a day's strike on 21st February, 1995;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what steps have been taken by Government to redress their grievances and to resolve the issues involved?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA) : (a) to (c) All the unions representing marketing workmen in Bharat Petroleum Corpn. Ltd. (BPCL) served strike notices for early finalisation of Long-Term wage settlement and promotion Policy. Similarly, some of the unions of Hindustan Petroleum Corpn. Ltd. (HPCL), except, South Zone and Visakh Refinery, issued strike notices dated 1st February, 1995 demanding delinking of productivity in Long-Term settlement. Inspite of conciliation meetings by the Dy. Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, the workmen went on one day strike on 21-2-95. During the strike uninterrupted supplies were maintained with the help of Officer.

As a result of conciliation and bipartite discussions in both the corporations, the workmen have since resumed normal duties. BPCL has signed a Memorandum of understanding with 12 out of 14 unions on All India basis.

गैस अॅथारिटी आॅफ इंडिया लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

2535. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अॅथारिटी आॅफ इंडिया लि॰ की स्थापना प्राकृतिक गैस के उत्पादन के पश्चात् के कार्यों में सुधार लाने तथा उन्हें नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1994 तक इस संगठन में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संगठन को शुद्ध लाभ के रूप में कितनी औसत वार्षिक कमाई हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैस अॅथारिटी आॅफ इंडिया लि॰ द्वारा देश की विद्युत और उर्वरक परियोजनाओं को बेहतर गुणवत्ता वाली गैस की आपूर्ति की जा रही है जिसका इन परियोजनाओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आवश्यकतानुसार बेहतर गुणवत्ता वाली गैस की आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) गेल की स्थापना प्राकृतिक गैस के परिवहन, उपचार, संसाधन, प्रभाजन, वितरण और विपणन के मुख्य उद्देश्यों के लिए की गई थी।

(ख) 01.04.94 की स्थिति के अनुसार चुकता पूंजी 845.32 करोड़ रुपए है। पिछले तीन वर्षों में कर पश्चात् निवल लाभ निम्नवत् था :

1991-92	—	93.55 करोड़ रुपए
1992-93	—	210.53 करोड़ रुपए
1993-94	—	320.54 करोड़ रुपए

(ग) और (घ) विद्युत और उर्वरक परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति से पूर्व जहां व्यवहार्य हो, वहां एल॰पी॰जी॰, सी 2/सी 3 आदि जैसे उच्चतर प्रेरणान निकाले जाते हैं। कुछ और निकर्षण संयंत्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।